+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS
(आज का विश्लेषण)
(03 September 2024)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- सुप्रीम कोर्ट ने जिस 'बुलडोजर न्याय' पर सवाल खड़े किये, वह क्या है?
- केंद्र सरकार द्वारा 'डिजिटल कृषि मिशन' को मंजूरी
- चीनी सामानों की भरमार से **MSME** को खतरा: **GTRI**
- **MCQs**

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

सुप्रीम कोर्ट ने जिस 'बुलडोजर न्याय' पर सवाल खड़े किये, वह क्या है?

परिचय:

- सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने, 2 सितंबर को "बुलडोजर न्याय" के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, इस मुद्दे पर दिशा-निर्देश निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा।
- न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि किसी भी संपत्ति को सिर्फ़ इसलिए ध्वस्त नहीं किया जा सकता क्योंकि अभियुक्त किसी आपराधिक मामले में शामिल है। पीठ ने कहा, *"भले ही वह दोषी हो, फिर भी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता*"।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह इस सन्दर्भ में अखिल भारतीय स्तर पर कुछ दिशा-निर्देश निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है ताकि मुद्दों के बारे में चिंताओं का ध्यान रखा जा सके।

- हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने स्पष्ट किया कि वह अवैध निर्माण का बचाव नहीं कर रहा है। "हम सार्वजनिक सड़कों को बाधित करने वाले किसी भी अवैध ढांचे का बचाव नहीं करेंगे, लेकिन विध्वंस के लिए दिशा-निर्देश होने चाहिए"।

क्या है 'बुलडोजर न्याय'?

- 'बुलडोजर न्याय', जिसे बुलडोजर राजनीति के रूप में भी जाना जाता है, कथित अपराधियों, सांप्रदायिक हिंसा के दंगाइयों और आरोपी अपराधियों के घरों को ध्वस्त करने के लिए भारी-भरकम मशीनरी का उपयोग करने की प्रथा को संदर्भित करता है।
- 'बुलडोजर न्याय' के हिस्से के रूप में, पूरे भारत में घरों, दुकानों और छोटे प्रतिष्ठानों को बुलडोजर से गिराया गया है, खासकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम और महाराष्ट्र राज्यों में।
- हालांकि, इस प्रथा की कड़ी आलोचना हुई है, जिसमें कई लोगों ने सवाल उठाया है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप साबित होने से पहले ही कार्रवाई कैसे की जा सकती है। साथ ही प्रशासन को एक व्यक्ति के अपराध के लिए पूरे परिवार को क्यों दंडित करना चाहिए।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

'बुलडोजर न्याय' पहली बार कब सामने आया?

- सितंबर 2017 में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के कुछ महीने बाद, योगी आदित्यनाथ ने अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल करने के बारे में चेतावनी जारी की। तब उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया गया था, "मेरी सरकार महिलाओं और समाज के कमज़ोर वर्गों के खिलाफ़ अपराध करने की सोच रखने वाले किसी भी व्यक्ति के घर को बुलडोजर से गिरा देगी।"
- बताया जाता है कि सत्ता में आने के बाद, योगी ने बुलडोजर की मदद से राज्य में भू-माफियाओं के चंगुल से 67,000 एकड़ से ज़्यादा सरकारी ज़मीन को मुक्त कराया।
- उल्लेखनीय "बुलडोजर न्याय" ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक राजनीतिक ब्रांड बनाने और अपराध के खिलाफ सख्त मुख्यमंत्री की छवि बनाने में मदद की, खासकर ऐसे राज्य में जहाँ कानून का शासन ढीला-ढाला माना जाता था।
- योगी आदित्यनाथ के उपायों की लोकप्रियता को देखते हुए, अन्य भाजपा सरकारों और यहाँ तक कि कुछ राज्यों में विपक्ष द्वारा शासित सरकारों ने भी इसी तरह

तत्काल "न्याय" किया। हालांकि, विध्वंस करने वाले अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने जो ढाँचे गिराए वे अवैध थे।

बुलडोजर न्याय की आलोचना:

- उल्लेखनीय है कि 'बुलडोजर न्याय' को काफी आलोचना मिली है और कई लोगों ने इन ध्वस्तीकरणों की वैधता पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर ने कहा, "बुलडोजर न्याय कानून के सभी सिद्धांतों के विपरीत है। किसी व्यक्ति के घर को केवल इसलिए नहीं गिराया जा सकता क्योंकि उसने सांप्रदायिक हिंसा या दंगे में भाग लिया है या कोई अवैध कार्य किया है"।
- 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने घरों पर बुलडोजर चलाने के मामले में यूपी सरकार की कार्रवाई पर चिंता जताई थी।
- इसके अलावा, फरवरी में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय और कानून के सिद्धांतों का पालन किए बिना संपत्ति को ध्वस्त करने के लिए उज्जैन के स्थानीय प्रशासन की खिंचाई की थी। इसने कहा, "स्थानीय प्रशासन के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किए बिना कार्यवाही करके किसी भी घर को ध्वस्त करना और अखबारों में ध्वस्तीकरण का प्रचार करना फैशन बन गया है"।

केंद्र सरकार द्वारा 'डिजिटल कृषि मिशन' को मंजूरी:

परिचय:

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 सितंबर को 2,817 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी।
- इस मिशन को डिजिटल कृषि पहलों का समर्थन करने के लिए एक व्यापक योजना के रूप में माना जाता है, जैसे कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण, डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES) को लागू करना और केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों द्वारा अन्य आईटी पहलों को आगे बढ़ाना।

डिजिटल कृषि मिशन क्या है?

- कृषि क्षेत्र में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने का मिशन अन्य क्षेत्रों में सरकार की प्रमुख ई-गवर्नेंस पहलों के समान है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में आधार, डिजीलॉकर, ई-हस्ताक्षर (इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा), एकीकृत

भुगतान इंटरफेस (UPI) और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसे डिजिटल समाधान सामने आए हैं।

- डिजिटल कृषि मिशन के तहत DPI के तीन प्रमुख घटकों की परिकल्पना की गई है: एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (DSS), और मृदा प्रोफ़ाइल मानचित्र। इनमें से प्रत्येक DPI घटक ऐसे समाधान प्रदान करेगा जो किसानों को विभिन्न सेवाओं तक पहुँचने और उनका लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा।
- इस मिशन का उद्देश्य एक तकनीक-आधारित पारिस्थितिकी तंत्र, डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES) बनाना भी है, जो कृषि उत्पादन का सटीक अनुमान प्रदान करेगा।

डिजिटल कृषि मिशन के लिए फंडिंग:

- इस मिशन के लिए 2,817 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है, जिसमें से 1,940 करोड़ रुपये केंद्र द्वारा और बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) द्वारा प्रदान किए जाएंगे।
- इस मिशन का शुभारंभ कृषि मंत्रालय की नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के लिए नियोजित गतिविधियों का हिस्सा है। मिशन को अगले दो वर्षों (2025-26 तक) में पूरे देश में लागू किया जाएगा।

- पहले मिशन को वित्तीय वर्ष 2021-22 में लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के प्रकोप यह संभव नहीं हो सका। भारत सरकार ने बाद में केंद्रीय बजट 2023-24 और 2024-25 दोनों में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण की घोषणा की।

डिजिटल कृषि मिशन के तीन स्तंभ:

(i) एग्रीस्टैक:

- किसान-केंद्रित DPI एग्रीस्टैक में तीन मूलभूत कृषि-क्षेत्र रजिस्ट्री या डेटाबेस शामिल हैं:
- किसान रजिस्ट्री:
  - ➢ किसानों को आधार के समान एक डिजिटल पहचान ('किसान आईडी') दी जाएगी, जिसे भूमि के रिकॉर्ड, पशुधन के स्वामित्व, बोई गई फसलों, जनसांख्यिकीय विवरण, पारिवारिक विवरण, योजनाओं और प्राप्त लाभों आदि से गतिशील रूप से जोड़ा जाएगा।
  - ➢ सरकार का लक्ष्य 11 करोड़ किसानों के लिए डिजिटल पहचान बनाना है, जिनमें से 6 करोड़ को चालू (2024-25) वित्तीय वर्ष में, अन्य 3 करोड़ को 2025-26 में और शेष 2 करोड़ किसानों को 2026-27 में शामिल किया जाएगा।

➢ एक बार रजिस्ट्री बन जाने के बाद, किसान लाभ और सेवाओं तक पहुँचने के लिए खुद को डिजिटल रूप से पहचान और प्रमाणित कर सकेंगे, बोझिल कागजी कार्रवाई से बचेंगे और उन्हें विभिन्न कार्यालयों या सेवा प्रदाताओं के पास शारीरिक रूप से जाने की बहुत कम या कोई आवश्यकता नहीं होगी।

- बोई गई फसल रजिस्ट्री:
  - ➢ बोई गई फसल रजिस्ट्री किसानों द्वारा लगाई गई फसलों का विवरण प्रदान करेगी। प्रत्येक फसल सीजन में डिजिटल फसल सर्वेक्षण - मोबाइल आधारित जमीनी सर्वेक्षण - के माध्यम से जानकारी दर्ज की जाएगी।
  - ➢ बोई गई फसल रजिस्ट्री विकसित करने के लिए 2023-24 में 11 राज्यों में एक पायलट डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया गया था।
  - ➢ सरकार का लक्ष्य अगले दो वर्षों में पूरे देश में डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू करना है, जिसमें चालू (2024-25) वित्तीय वर्ष में 400 जिले और शेष वित्त वर्ष 2025-26 में शामिल होंगे।
- भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र: मानचित्र भूमि अभिलेखों पर भौगोलिक जानकारी को उनके भौतिक स्थानों से जोड़ेंगे।

(ii) कृषि DSS:

- कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, जिसका हाल ही में अनावरण किया गया, फसलों, मिट्टी, मौसम और जल संसाधनों आदि पर रिमोट सेंसिंग-आधारित जानकारी को एकीकृत करने के लिए एक व्यापक भू-स्थानिक प्रणाली बनाएगी।
- यह जानकारी बोए गए फसल पैटर्न, सूखे/बाढ़ की निगरानी और किसानों द्वारा फसल बीमा दावों के निपटान के लिए प्रौद्योगिकी-/मॉडल-आधारित उपज मूल्यांकन की पहचान करने के लिए फसल मानचित्र निर्माण का समर्थन करेगी।

(iii) मृदा प्रोफाइल मानचित्रण:

- इस मिशन के तहत, लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि के विस्तृत मृदा प्रोफ़ाइल मानचित्र (1:10,000 पैमाने पर) तैयार किए जाने की परिकल्पना की गई है। लगभग 29 मिलियन हेक्टेयर की विस्तृत मृदा प्रोफ़ाइल सूची पहले ही पूरी हो चुकी है।

डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES):

- DGCES मौजूदा फसल उपज अनुमान प्रणाली को बेहतर बनाने और डेटा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम होगा, जो भारत के कृषि उत्पादन अनुमानों की सटीकता के बारे में कभी-कभी उठाई जाने वाली चिंताओं को संबोधित करेगा।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- एक बेहतर डेटा सरकारी एजेंसियों को कागज रहित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) आधारित खरीद, फसल बीमा और क्रेडिट कार्ड से जुड़े फसल ऋण जैसी योजनाओं और सेवाओं को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने और उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए सिस्टम विकसित करने में मदद करेगा।
- DGCES-आधारित उपज और रिमोट-सेंसिंग डेटा के साथ-साथ बोए गए फसल क्षेत्र पर डिजिटल रूप से कैप्चर किए गए डेटा से फसल उत्पादन अनुमानों की सटीकता में सुधार करने में मदद मिलेगी। इससे प्राप्त डेटा फसल विविधीकरण को सुविधाजनक बनाने और फसल और मौसम के अनुसार सिंचाई की जरूरतों का मूल्यांकन करने में भी मदद करेगा।

चीनी सामानों की भरमार से MSME को खतरा: GTRI

चर्चा में क्यों है?

- थिंक टैंक 'ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI)' की 1 सितंबर को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, छाते, कांच के बने पदार्थ, कटलरी, हैंडबैग और सौंदर्य प्रसाधन जैसे विभिन्न उत्पाद श्रेणियों में काम करने वाले भारतीय छोटे व्यवसायों को चीनी सामानों के आगमन के कारण घरेलू बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।
- उल्लेखनीय है कि सस्ते चीनी सामान के कारण MSME के लिए बाजार में टिके रहना मुश्किल हो जाता है, जिससे उन्हें अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये चुनौतियां भारत में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं।

चीनी आयात का प्रभुत्व स्थानीय उत्पादन को विस्थापित कर रहा:

- चीनी आयात का प्रभुत्व स्थानीय उत्पादन को विस्थापित कर रहा है, क्योंकि भारत में इस्तेमाल होने वाले 90 प्रतिशत से अधिक छाते, कृत्रिम फूल और मानव

बाल के सामान चीन से आते हैं। कांच के बने पदार्थ, चमड़े और खिलौनों जैसी उत्पाद श्रेणियों में, इन वस्तुओं के लिए भारत के कुल बाजार में चीन की हिस्सेदारी बढ़कर 50 प्रतिशत से अधिक हो गई है।

- यहां तक कि सिरेमिक उत्पादों (51.4 प्रतिशत) और संगीत वाद्ययंत्र (51.2 प्रतिशत) में भी, जहां भारतीय कारीगर कभी फलते-फूलते थे, चीनी आयात का प्रभुत्व स्थानीय उत्पादन को विस्थापित कर रहा है, यह कहा।
- इस रिपोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि चीन से भारत के औद्योगिक सामान आयात बढ़ रहे हैं। जनवरी से जून 2024 तक भारत ने चीन को 8.5 बिलियन डॉलर का निर्यात किया जबकि 50.4 बिलियन डॉलर का आयात किया, जिसके परिणामस्वरूप 41.9 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा हुआ।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन से आयात का लगभग 98.5 प्रतिशत या 49.6 बिलियन डॉलर औद्योगिक सामान है। भारत के औद्योगिक सामान आयात में चीन की हिस्सेदारी 29.8 प्रतिशत है और वह सभी आठ औद्योगिक सामान श्रेणियों में शीर्ष आपूर्तिकर्ता है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

भारत की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए खतरा:

- चीनी आयात पर भारी निर्भरता भारतीय MSME की बाजार हिस्सेदारी और अस्तित्व को खत्म कर रही है। ऐसे में इन छोटे व्यवसायों की रक्षा और भारत की आर्थिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना आवश्यक है।
- GTRI ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कच्चे तेल और कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधनों में व्यापार घाटा कम चिंताजनक है, लेकिन आयातित औद्योगिक वस्तुओं पर बढ़ती निर्भरता भारत की आर्थिक संप्रभुता को खतरे में डालती है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

MCQs

1. चर्चा में रहे 'बुलडोजर न्याय' संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

   1. यह कथित अपराधियों, सांप्रदायिक हिंसा के दंगाइयों और आरोपी अपराधियों के घरों को ध्वस्त करने के लिए भारी-भरकम मशीनरी का उपयोग करने की प्रथा को संदर्भित करता है।
   2. सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार किसी भी संपत्ति को सिर्फ़ इसलिए ध्वस्त नहीं किया जा सकता क्योंकि अभियुक्त किसी आपराधिक मामले में शामिल है।

   उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   (a) केवल 1

   (b) केवल 2

   (c) 1 और 2 दोनों

   (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

   Ans:(c)

2. हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने परिव्यय राशि की डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है?

   (a) 1,940 करोड़ रुपये
   (b) 2,817 करोड़ रुपये
   (c) 5200 करोड़ रुपये
   (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

   Ans:(b)

3. चर्चा में रहे 'डिजिटल कृषि मिशन' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इस मिशन का एक उद्देश्य डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण बनाना भी है, जो कृषि उत्पादन का सटीक अनुमान प्रदान करेगा।
2. इस मिशन के तहत DPI के चार प्रमुख घटकों की परिकल्पना की गई है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans:(a)

4. हाल ही में चर्चा में रहे डिजिटल कृषि मिशन के तहत स्थापित 'किसान रजिस्ट्री' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/ से कथन सही है/हैं?

(a) किसानों को आधार के समान एक डिजिटल पहचान दी जाएगी।
(b) सरकार का लक्ष्य 11 करोड़ किसानों के लिए डिजिटल पहचान बनाना है।
(c) इसके माध्यम से किसान सेवाओं तक पहुँचने के लिए खुद को डिजिटल रूप से पहचान और प्रमाणित कर सकेंगे, बोझिल कागजी कार्रवाई से बच सकेंगे।
(d) उपर्युक्त सभी सही कथन है।

Ans:(d)

5. हाल में चर्चा में रहे 'भारत-चीन व्यापार की चुनौतियों' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. सस्ते चीनी सामान की भारतीय बाजारों में भरमार के कारण MSME को अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
2. ऐसे में इन छोटे व्यवसायों की रक्षा और भारत की आर्थिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना आवश्यक है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans: (c)